आत्मनिर्भरता से आपूर्ति मजबूत : पीयूष

जिनेवा में कहा, लागत से ज़्यादा अब लचीलेपन और भरोसे को प्राथमिकता ; जर्मनी के दौरे पर रहेंगे मंत्री

नई दिल्ली/जिनेवा. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (ग्लोबल सप्लाई चेन) में उजागर हुई कमज़ोरियों से निपटने के लिए भारत द्वारा %आत्मनिर्भरता% का मार्ग चुनने पर ज़ोर दिया है.

जिनेवा में यूएनसीटीएडी के मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि भारत की रणनीति अब लागत दक्षता (कॉस्ट एफिशिएंसी) के बजाय लचीलेपन (रेज़िलिएंस) और भरोसे को प्राथमिकता देती है.गोयल ने कहा, हमने महसूस किया है कि हमें अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर फिर से विचार करना होगा. उन्होंने बताया कि सरकार हर क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला की समीक्षा कर रही है ताकि कमज़ोरियों का पता लगाया जा सके और क्षमता का विस्तार किया जा सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता के बावजूद, भारत ने दुनिया भर के अनुकूल देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (स्नञ्ज) और व्यापारिक संबंध बढ़ाना जारी रखा है, ताकि आवश्यक उपकरण और घटक मिलते रहें. उन्होंने कहा, इसलिए हमने केवल लागत के बजाय भरोसे और विश्वसनीयता को अधिक महत्व दिया है. गोयल ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह विकासशील देशों के बीच सहयोग को वैश्विक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण मानता है. उन्होंने भुगतान प्रणालियों जैसे डिजिटल नवाचारों को साझा करने का सुझाव दिया, जो लेनदेन की लागत को काफी कम कर सकते हैं.

अपने जिनेवा संबोधन के तुरंत बाद, मंत्री पीयूष गोयल व्यापार और निवेश संबंधों को मज़बूत करने के लिए 23 अक्टूबर से जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे.

सुरक्षा के लिए अतिरिक्त भुगतान को तैयार

गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन लाने के लिए फ्अतिरिक्त पैसा देने को तैयार हैफ्. उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण ने देश के भीतर रोज़गार सृजित करने और उत्पादन क्षमताओं के निर्माण में मदद की है. मंत्री ने कहा कि जहाँ भी किसी एक भूगोल से उत्पादन या आपूर्ति की अत्यधिक निर्भरता पाई गई, वहाँ आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया.

भारत की पीएलआई नीति पर चीन ने डब्ल्यू टी ओ में जताई आपत्ति

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की विनिर्माण प्रोत्साहन नीति पर चीन की कुछ आपत्तियों को लेकर विवाद निपटान फोरम में परामर्श की कार्रवाई शुरू की है.

डब्ल्यूटीओ ने कहा कि चीन ने भारत में उन्नत रसायन सेल बैटरियों, वाहनों और वाहनों के कल-पुर्जों तथा इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रोत्साहन जैसे उपायों पर परामर्श किये जाने की अपील की थी. चीन का यह अनुरोध 15 अक्टूबर को भारत को भेज दिया गया था और 20 अक्टूबर को इस मुद्दे पर परामर्श के लिए विवाद निपटान फोरम को सक्रिय कर दिया गया है.

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विकास

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर. बिजली पारेषण व्यवस्था के मोर्चे पर सुधार की 2.4 लाख करोड़ रुपये की योजना के माध्यम से सरकार देश में पांच लाख मेगावाट बिजली के लिए मजबूत पारेषण नेटवर्क की कल्पना कर रही है. पारेषण प्रणाली में सुधार के जरिये नवीकरणीय ऊर्जा-समृद्ध राज्यों को बिजली की बड़ी मांग वाली जगहों से जोड़ा जायेगा.

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि सरकार हरित ऊर्जा गलियारों और राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से नयी उच्च क्षमता वाली पारेषण लाइनों के माध्यम से पारेषण बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता दे रही है. उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2030 तक पांच लाख मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है. मंत्रालय का कहना है कि ट्रांसमिशन में सुधार की ये परियोजनाएं कई वर्षों में पूरी होंगी, लेकिन एक बार चालू होने पर ये दो लाख मेगावाट से अधिक नयी नवीकरणीय क्षमता जोड़ेंगी. इस प्रकार वर्तमान चरण अस्थायी है - एक संक्रमणकालीन अंतराल है, न कि एक संरचनात्मक सीमा है.

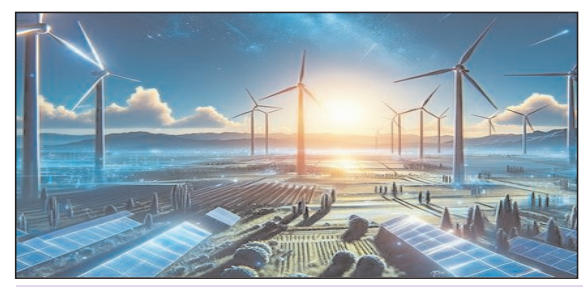

मंत्रालय के अनुसार, साल 2030 स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को कार्यनीति स्तर पर स्थायित्व के साथ आगे बढ़ाने के लिए ग्रिड, वित्तीय प्रणालियों और बाजार डिजाइन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा का समन्वयन किया जा रहा है. विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार ने पहले ही एचवीडीसी कॉरिडोर बनाने और अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को वर्तमान 120 गीगावाट (1.2 लाख मेगावाट) से बढ़ाकर साल 2027 तक 1.43 लाख मेगावाट तथा 2032 तक 1.68 लाख मेगावाट करने की योजना बना ली है.

सेंसेक्स-निफ्टी रिकॉर्ड पर

मुंबई, 22 अक्टूबर. बलिप्रतिपदा के पावन अवसर पर बुधवार को देश के वित्तीय हृदय मुंबई में शेयर बाजार और मुद्रा बाजार पूरी तरह से बंद रहे. कारोबारी सप्ताह में यह लगातार दूसरा दिन था जब बाजारों में अवकाश रहा, क्योंकि एक दिन पहले दिवाली पर भी नियमित ट्रेडिंग नहीं हुई थी.

महाराष्ट्र और देशभर में आज बलिप्रतिपदा पर्व की धूम रही, और इस अवसर पर देश के प्रमुख वित्तीय बाजार शेयर बाजार और मुद्रा बाजार बंद रहे. कारोबारियों के अनुसार, त्योहारों की श्रृंखला के कारण लगातार दूसरे दिन निवेशकों को बाजार से अवकाश मिला. दिवाली के अगले दिन मनाई जाने वाली बलिप्रतिपदा महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बड़े उत्सव के रूप में मनाई जाती है. इसे अन्नकूट और पड़वा भी कहा जाता है.

इसे देखते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों बंद रहे. हालांकि, मंगलवार को दिवाली के दिन बाजार बंद रहे थे, लेकिन निवेश की परंपरा निभाते हुए एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया गया था. इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी-50 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए. सेंसेक्स में 300 से अधिक अंकों की बढ़त देखी गई. यह सेशन प्रतीकात्मक होता है, लेकिन निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए यह शुभ संकेत माना जाता है.

सम्मेलन के लिए यूएई जाएंगे चंद्रबाबू नायडू

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू निवेशकों और वैश्विक उद्योगपतियों को सीआईआई साझेदारी सम्मेलन के लिए आमंत्रित करने संयुक्त अरब अमीरात की तीन दिवसीय यात्रा पर 22 अक्टूबर को रवाना होंगे. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू 14-15 नवंबर को विशाखापत्तनम में होने वाले सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे. यह दौरा 22 से 24 अक्टूबर तक होगा, जिसका उद्देश्य वैश्विक निवेशकों को आमंत्रित करना और राज्य में निवेश बढ़ाना है.मुख्यमंत्री 22 अक्टूबर को हैदराबाद से दुबई के लिए उड़ान भरेंगे. वह उसी दिन एक रोड शो में भाग लेंगे.

बंदरगाह परियोजना लिए समीक्षा बैठक

सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद निर्माण कार्य फिर शुरू

वधावन पोर्ट परियोजना की अनुमानित लागत 76,000 करोड

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर. महाराष्ट्र के पालघर में बन रहे वधावन मेगा पोर्ट की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार के तीन कैबिनेट मंत्रियों ने एक उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक ऐसे समय हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में परियोजना पर रोक लगाने की याचिका खारिज की है.

महाराष्ट्र के पालघर में निर्माणाधीन वधावन बंदरगाह परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार के तीन प्रमुख मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की. उनके साथ जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी उपस्थित थे.

बैठक में संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में परियोजना पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया. याचिका कुछ स्थानीय कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय चिंताओं के आधार पर दायर की गई थी. खारिज होने के साथ ही बंदरगाह निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है. वधावन पोर्ट परियोजना की अनुमानित लागत 76,000 करोड़ है.

भार्गव का इस्तीफा मंजूर नहीं रहेंगे मैनेजमेंट में

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर. देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के एक वरिष्ठ चेहरे ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है. कस्टमर एक्सपीरियंस निदेशक शिवन भार्गव ने 15 साल के लंबे और गौरवशाली कार्यकाल के बाद पद छोड़ने का ऐलान किया है. यह कदम ऐसे समय आया है जब दूरसंचार उद्योग में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा और बदलाव चल रहा है.

भारती एयरटेल लिमिटेड के निदेशक (कस्टमर एक्सपीरियंस) शिवन भार्गव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और आने वाले 3 से 4 महीनों में वह कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन से अलग हो जाएंगे.

शिवन भार्गव ने अपना इस्तीफा कंपनी के सीईओ शाश्वत शर्मा के नाम सौंपा. पत्र में उन्होंने लिखा कि वह संगठन के बाहर अपने पेशेवर लक्ष्यों की तलाश करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया है.

ईपीएफओ में सुधार

कर्मचारियों को मिलेगा अधिक अधिकार

75 प्रतिशत तक की राशि बिना किसी दस्तावेज के निकाल सकते हैं

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर. सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों में किए गए व्यापक सुधारों को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित मंच स्कोप ने इसे कर्मचारी सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम करार दिया है. स्कोप का कहना है कि इन बदलावों से निकासी प्रक्रिया सरल, त्वरित और पारदर्शी हो गई है.

देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का शीर्ष निकाय स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने केंद्र सरकार द्वारा नियमों में किए गए हालिया बदलावों को कर्मचारी हितैषी और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने वाला बताया है. स्कोप के अनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 13 जटिल प्रावधानों को सिर्फ तीन श्रेणियों में समाहित करना एक ऐसा सुधार है जो भविष्य निधि से निकासी की प्रक्रिया को पहले की तुलना में काफी सरल और तेज बनाएगा.

स्कोप का कहना है कि अब कर्मचारी सिर्फ एक वर्ष की सेवा के बाद ही भविष्य निधि से 75 प्रतिशत तक की राशि बिना किसी दस्तावेज के निकाल सकते हैं.

मुंबई से मदीना की सीधी उड़ान

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर. भारत से मदीना जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन इंडिगो अब मुंबई से सऊदी अरब के मदीना शहर के लिए सीधी और दैनिक उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है. यह पहली बार होगा जब मुंबई से मदीना के लिए कोई सीधी फ्लाइट चलाई जाएगी.

विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने ऐलान किया है कि वह 15 नवंबर 2025 से मुंबई से मदीना के लिए सीधी दैनिक उड़ान शुरू करेगी. यह सेवा सऊदी अरब के धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर मदीना को मुंबई से सीधे जोड़ेगी. इंडिगो ने बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में जानकारी दी कि इस नई उड़ान के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है. इस रूट पर कंपनी एयरबस,320 विमान का संचालन करेगी.

इंडिगो ने बताया कि मुंबई से मदीना के बीच की यह पहली सीधी उड़ान होगी. इससे पहले मदीना के लिए हैदराबाद, दिल्ली या अन्य अंतरराष्ट्रीय हब्स से कनेक्शन उड़ानें उपलब्ध थीं.

बीमा कंपनियों की भूमिका है वित्तीय सुरक्षा

सुरक्षा कवर के अंतर को पाटने में बीमा कंपनियों की भूमिका अहम : आलोक अग्रवाल

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर: भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा में वित्तीय मजबूती उतनी ही जरूरी है जितना जीडीपी की वृद्धि. बीमा क्षेत्र में व्याप्त सुरक्षा कवर का अंतर देश की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए एक बड़ी चुनौती है.

ज्यूरिख कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ, आलोक अग्रवाल ने कहा कि सामान्य बीमा उत्पाद इस अंतर को भरने और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. अग्रवाल ने बताया कि हेल्थ, लाइफ, मोटर, होम, फसल और जलवायु जोखिम से जुड़े बीमा उत्पाद देश की वित्तीय मजबूती में योगदान दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों को सिर्फ नए उत्पाद लाने पर नहीं, बल्कि लोगों में जागरूकता और भरोसा बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए. इसके लिए स्थानीय भाषाओं में जानकारी देना, स्थानीय प्रभावशाली लोगों के साथ साझेदारी और सरकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत व पीएमएफबीवाई के साथ सहयोग महत्वपूर्ण हैं. आलोक अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि वित्तीय साक्षरता और जागरूकता बढ़ाने के लिए फिनटेक, एग्रीटेक, एमएसएमई और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग आवश्यक है.

समाचार विशेष

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लड़ने का फैसला किया

राज्य की सभी चार सीटों पर उम्मीदवार उतारे

जम्मू. लोकप्रिय धारणा से उलट अब्दुल्ला पिता पुत्र ने भाजपा और केंद्र सरकार के सामने झुक कर समझौता करने की बजाय लड़ने का रास्ता चुना है. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य की सभी चार राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है. फारूक और उमर अब्दुल्ला को पता है कि चौथी सीट जीतने के लिए भाजपा को हराना होगा.

ध्यान रहे भाजपा ने भी सभी सीटों पर लड़ने का फैसला किया है लेकिन उसको पता है कि लड़ाई सिर्फ एक सीट पर होनी है. बाकी तीन सीटें स्वाभाविक रूप से सत्तारूढ़ दल को मिलेंगी. चुनाव की अधिसूचना इस हिसाब से जारी होती है, जिससे सत्तारूढ़ दल या गठबंधन को फायदा होता है. पहली दो सीटों की अधिसूचना अलग अलग जारी हुई है. ये सीटें जीतने के लिए 45-45 वोट की जरुरत है. बाकी दो सीटों की अधिसूचना एक साथ जारी हुई तो उनको जीतने के लिए 30-30 वोट की जरुरत है. पहले लग रहा था कि कोई टकराव नहीं होगा. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी पार्टी के तीन उम्मीदवार उतारेंगे और चौथी सीट भाजपा के लिए छोड़ देंगे, जिसके 28 विधायक हैं. लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. इसलिए 24 अक्टूबर को राज्यसभा की सभी चार सीटों पर चुनाव होंगा.

सबसे हैरान करने वाली बात कांग्रेस की रही, जिसने चौथी सीट पर लड़ने की हिम्मत नहीं की. उमर अब्दुल्ला ने पहले तीन ही उम्मीदवारों की घोषणा की थी. चौथी सीट वे कांग्रेस के लिए छोड़ना चाहते थे. लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कारा ने कहा कि भाजपा के 28 विधायक हैं इसलिए वह सीट जीतने की संभावना नहीं है.

हार के डर से कांग्रेस ने चौथी सीट नहीं ली

चौथा उम्मीदवार उतारने के बाद उमर ने कहा कि यह सीट जीतने का सबसे अच्छा मौका कांग्रेस के लिए था लेकिन वह तैयार नहीं हुई. अब उमर ने इस चुनाव को कश्मीरी पहचान से जोड़ दिया है. उन्होंने कहा है कि भाजपा के 28 विधायक हैं और सीट जीतने के लिए 30 वोट की जरुरत है. अगर कश्मीर की पार्टियों के विधायक अपना वोट भाजपा को नहीं देते हैं तो भाजपा नहीं जीतेगी. हालांकि वे खुद इस बात से चिंतित हैं कि भाजपा ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं तो इसका मतलब है कि वह पैसे और ताकत के दम पर क्रॉस वोटिंग कराने का प्रयास करेगी.

भाजपा ने बाबूलाल सोरेन पर जताया भरोसा

आदिवासी वोट बैंक साधने की तैयारी ; झामुमो से होगा सीधा मुकाबला

जमशेदपुर. झारखंड की राजनीति में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई इस सीट पर अब सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं. इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित करते हुए एक बार फिर बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताया है.

भाजपा ने बाबूलाल सोरेन को घाटशिला सीट से आधिकारिक उम्मीदवार बनाकर यह संकेत दिया है कि पार्टी स्थानीय समीकरणों और आदिवासी मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही है. 2024 के विधानसभा चुनाव में भी बाबूलाल सोरेन ने भाजपा के टिकट पर इस सीट से दमदार प्रदर्शन किया था. बाबूलाल सोरेन ने टिकट मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया है.

भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई

भाजपा ने इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया है. बताया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व की नजर लगातार चुनावी गतिविधियों पर बनी हुई है, जबकि संगठन स्तर पर भी बूथ प्रबंधन से लेकर जनसंपर्क अभियान तक की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. उधर, सत्ता पक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) भी अपने प्रत्याशी की घोषणा जल्द करने की तैयारी में है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि घाटशिला का उपचुनाव भाजपा और झामुमो के बीच एक सीधा मुकाबला होगा, जिसमें स्थानीय मुद्दे, जनभावनाएं और जातीय समीकरण अहम भूमिका निभाएंगे.

बागी बिगाड़ेंगे खेल या करेंगे कमाल

गोपालगंज में सियासी समीकरण हुए दिलचस्प

गोपालगंज. बिहार विधानसभा चुनाव-2025 की आहट के साथ ही गोपालगंज जिले की तीन प्रमुख विधानसभाओं बैकुंठपुर, बरौली और गोपालगंज सदर में सियासी हलचल तेज हो गई है. इस बार मैदान में बागी उम्मीदवारों की सक्रियता ने चुनावी समीकरणों को पूरी तरह उलझा दिया है. सवाल उठ रहा है कि क्या बागी खेल बिगाड़ेंगे या राजनीति में नया कमाल करेंगे.

बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने दमदार एंट्री ली है. लेकिन टिकट न मिलने से नाराज विकास सिंह और सेवानिवृत्त डीआईजी रामनारायण सिंह ने बागी तेवर अपनाते हुए मैदान में उतरने का ऐलान किया है. वहीं, राजद ने प्रेमशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है, लेकिन पार्टी से बागी पूर्व प्रमुख पति प्रदीप कुमार यादव बसपा के टिकट पर ताल ठोक चुके हैं. ऐसे में बैकुंठपुर का चुनावी मैदान अब त्रिकोणीय से कहीं अधिक जटिल हो गया है.

बरौली विधानसभा क्षेत्र में भी सियासी समीकरण बदल गए हैं. एनडीए ने यहां मंजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जबकि पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक रामप्रवेश राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का एलान किया है. राजद प्रत्याशी दिलीप सिंह को भी बागी पूर्व विधायक रेयाजुल हक राजू की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. गोपालगंज सदर में एनडीए ने जिला परिषद अध्यक्ष सुभाष सिंह को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वर्तमान विधायक कुसुम देवी ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रणनीति पर असर डाला है.

विशेष | **बिहार चुनाव में रणनीतिक बदलाव या राजनीतिक संकेत?**

भाजपा की स्टार प्रचारक लिस्ट से शाहनवाज़ गायब

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं.

पार्टी ने इस बिहार में प्रचार की जिम्मेदारी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी सौंपी है. बिहार के भी कई बड़े नेताओं को इस लिस्ट में जगह दी गई है. लेकिन इस लिस्ट से सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम गायब है.

कभी बिहार में बीजेपी का प्रमुख मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले शाहनवाज़ को न तो स्टार प्रचारक बनाया गया है और न ही उन्हें किसी सीट से उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया. यही वजह है कि यह फैसला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. पिछले कुछ हफ्तों से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी किशनगंज सीट से शाहनवाज़ हुसैन को मैदान में उतार सकती है. किशनगंज बिहार की उन कुछ सीटों में से एक है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. लेकिन, पार्टी ने वहां से एक नए चेहरे को उम्मीदवार बना दिया, जिससे यह साफ हो गया कि शाहनवाज़ इस बार न तो चुनाव मैदान में हैं और न ही प्रचार की पहली पंक्ति में.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शाहनवाज़ हुसैन जैसे अनुभवी नेता की अनुपस्थिति बीजेपी के लिए संदेशात्मक रूप से महत्वपूर्ण है. कई विशेषज्ञों का मानना है कि किशनगंज से शाहनवाज़ की उम्मीदवारी से बीजेपी को समावेशी राजनीति का संदेश देने में मदद मिल सकती थी, खासकर तब जब बिहार में मुस्लिम मतदाता लगभग 17 प्रतिशत हैं.

कोर वोटर एकजुटता पर फोकस

सियासी विश्लेषक मानते हैं कि इस बार एनडीए की रणनीति पूरी तरह से कोर वोटर एकजुटता पर केंद्रित है, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधित्व को प्रतीकात्मक स्तर पर भी सीमित रखा गया है. दूसरी ओर, विपक्षी महागठबंधन इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है. कांग्रेस और राजद दोनों पहले ही बीजेपी पर मुस्लिमों की उपेक्षा का आरोप लगा चुके हैं और शाहनवाज़ हुसैन को स्टार प्रचारक सूची से बाहर रखना उनके लिए एक नया राजनीतिक हथियार साबित हो सकता है.